



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 235]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 7, 2019/श्रावण 16, 1941

No. 235]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 7, 2019/SHRAVANA 16, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2019

मामला सं. एसएसआर 03/2019

विषय – कोरिया जनवादी गणराज्य, ताईवान और सउदी अरब से एसीटोन के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत

- फा.सं. 7/9/2019-डीजीटीआर.—**1. वर्ष 1995 और इसके पश्चात यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण एवं क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे यहां इसके बाद नियमावली कहा गया है) के संबंध में, निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) कोरिया जनवादी गणराज्य, ताईवान और सउदी अरब (जिन्हें इसके बाद सामूहिक रूप से संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “एसीटोन” (जिसे यहां इसके बाद संबद्ध वस्तु कहा गया है), के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को लागू करने की सिफारिश करते हैं।
2. रूस और कोरिया जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में मूल जांच प्राधिकारी द्वारा आरंभ की गई थी। तथापि, प्राधिकारी ने रूस के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं से संबंधित जांच को अधिसूचना सं. 14/13/2006 दिनांक 14 मार्च, 2008 के अनुसार समाप्त कर दिया। तत्पश्चात, कोरिया जन. गण. से आयातों के विरुद्ध निश्चयात्मक शुल्क को लागू करने की सिफारिश करते हुए प्राधिकारी द्वारा दिनांक 9 मई, 2008 की

अधिसूचना सं. 14/13/2006-डी जी ए डी के अनुसार अंतिम जांच परिणाम जारी किए गए। अंतिम जांच परिणामों में प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर दिनांक 10 जून, 2008 की अधिसूचना सं. 75/2008-सीमाशुल्क के अनुसार निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लागू किया गया। तत्पश्चात एक पुनरीक्षा जांच की गई और प्राधिकारी ने कोरिया जन. गण. से आयातों पर लागू शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की। वित्त मंत्रालय ने दिनांक 18 फरवरी, 2015 की अधिसूचना सं. 05/2015-सीमाशुल्क (ए डी डी) के अनुसार निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क का विस्तार किया।

3. जबकि, प्राधिकारी द्वारा ताइवान और सउदी अरब से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में मूल जांच आरंभ की गई थी और तत्पश्चात निश्चयात्मक शुल्क को लागू करने की सिफारिश करते हुए प्राधिकारी द्वारा दिनांक 22 जनवरी, 2015 की अधिसूचना संख्या 14/16/2012-डी जी ए डी के अनुसार अंतिम जांच परिणाम संबंधी अधिसूचना जारी की गई। अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर, दिनांक 16 अप्रैल, 2015 की अधिसूचना सं. 13/2015-सीमाशुल्क (एडीडी) के अनुसार निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लागू किया गया।
4. जबकि, अधिनियम और नियमों के अनुसरण में, एस आई ग्रुप इंडिया प्रा. लि., हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड और दीपक फेनोलिक्स लिमिटेड (जिन्हें यहां “याचिकाकर्ता” कहा गया है) ने कोरिया जन.गण., सउदी अरब और ताइवान से एसीटोन के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण को जारी रखने के लिए एक संयुक्त पुनरीक्षा याचिका दायर की है।
5. जबकि, तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर प्राधिकारी का मत है कि कोरिया जन.गण., ताइवान और सउदी अरब के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में प्रवृत्त शुल्कों के अधिरोपण को जारी रखने के लिए पुनरीक्षा की जरूरत है।

क. विचाराधीन उत्पाद

6. याचिका में विचाराधीन उत्पाद वही है जैसा कि मूल जांच में वर्णित है, जिसे अंतिम जांच परिणाम में निम्नानुसार परिभाषित किया गया था :-

“12. वर्तमान एस एस आर जांच तथा साथ ही मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) एसीटोन है। यह एकल ग्रेड में उत्पादित एक आधारभूत आर्गेनिक रसायन है। यह एक एग्रीएबल ईथर जैसी गंध वाला एक रंगहीन द्रव्य है। यह या तो विलायक अथवा मध्यवर्ती के रूप में बहुत से आर्गेनिक सिंथेसिस में प्रयुक्त किया जाता है। इसका बल्क फार्मास्युटीकल्स, एग्रीकेमिकल्स, डाइस्फल्स, कुछ विशिष्ट एक्सप्लोसिव्स और डाउन स्ट्रीम केमिकल्स के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। एसीटोन का प्रयोग विशेष रूप से इसोफोरोन, डायसिटोन, अल्कोहल, मिथाइल मेथाक्राइलेट और बिसफीनोल ए. के विनिर्माण में किया जाता है। इसके अतिरिक्त, इस का प्रयोग कुछ विशिष्ट रबड़ केमिकल्स अथवा ऑक्सी एसीटिलीन सेल्यूलोस एसीटेट के विनिर्माण में भी किया जाता है।”

7. चूंकि, यह जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है, विचाराधीन उत्पाद वही है जैसाकि पूर्व में आयोजित जांच में परिभाषित किया गया था। इसके अतिरिक्त, इस अवधि में कोई उल्लेखनीय घटनाक्रम घटित नहीं हुआ है।

ख. समान वस्तु

8. समान वस्तु के संबंध में नियम 2(घ) में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

“समान वस्तु” से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटन के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरूप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;

9. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुएं भौतिक और तकनीकी विनिर्देशन, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद संबंधी

विशेषताएं, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की शर्तों में तुलनीय है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय विशेषताएं हैं। प्रयोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं।

10. विचाराधीन उत्पाद का सीमा क्षेत्र वही रखा गया है जैसाकि पिछले अंतिम जांच परिणामों के समय निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा विचारित किया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को वर्तमान पुनरीक्षा जांच के प्रयोजनार्थ संबद्ध देशों से आयात की जा रही "समान वस्तुओं" के सदृश माना जा रहा है।

ग. घरेलू उद्योग

11. निर्णायक समीक्षा की शुरुआत के लिए याचिका एस आई ग्रुप इंडिया प्रा. लि., मै. हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड और दीपक फैनोलिक्स लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से दायर की गई है। याचिकाकर्ता कंपनियों का उत्पादन देश में संबद्ध वस्तुओं के भारतीय उत्पादन का 100 प्रतिशत है, क्योंकि भारत में संबद्ध वस्तुओं का कोई अन्य उत्पादक नहीं है।
12. प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता कंपनियों ने पी ओ आई के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है, हालांकि ये आयात शुल्क मुक्त योजना के तहत साथ ही बीज विपणन प्रयोजन के लिए हैं तथा घरेलू बाजार स्थिति को प्रभावित करने के लिए इसकी मात्रा महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए, प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता कंपनियों को नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थों के भीतर घरेलू उद्योग माना है और आवेदन संबंधित नियमावली के नियम 5 की शर्तों में योग्यता संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

घ. निर्णायक समीक्षा की शुरुआत

13. जबकि, प्रस्तुत किए गए विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन को ध्यान में रखते हुए और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा निर्णायक समीक्षा जाँच की शुरुआत करते हैं ताकि संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में लागू शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा की जा सके और इस बात की जाँच की जा सके कि क्या लागू शुल्क को हटाये जाने से पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

ड. संबद्ध देश

14. ये शुल्क कोरिया गण., ताइवान और सउदी अरब के विरुद्ध लागू हैं। पाटन के मौजूद रहने और क्षति के जारी रहने और उसकी संभावना के संबंध में रिकॉर्ड पर साक्ष्य को देखते हुए, वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच का कार्यक्षेत्र कोरिया गण., ताइवान और सउदी अरब को शामिल करेगा।

च. जांच अवधि

15. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पी ओ आई) 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 (12 महीने है) और क्षति जांच की अवधि अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016, अप्रैल, 2016 से मार्च 2017 और अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018 और पी ओ आई है। इसके अतिरिक्त, पाटन और क्षति की संभावना का निर्धारण करने के लिए पी ओ आई के बाद के आंकड़ों की भी जांच की जाएगी।

छ. प्रक्रिया

16. इस समीक्षा में ताइवान और सउदी अरब से एसीटोन के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू करने की सिफारिश करने वाली दिनांक 22 जनवरी, 2015 की अधिसूचना सं. 14/16/2012-डी जी ए डी के अनुसार प्रकाशित अंतिम जांच परिणाम के सभी पहलुओं और कोरिया जन.गण. से एसीटोन के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को लागू करने की सिफारिश करने वाली दिनांक 4 दिसंबर, 2014 की अधिसूचना सं. 15/13/2013-डी जी ए डी के अनुसार प्रकाशित

अंतिम जांच परिणाम के सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा। प्राधिकारी यथा अपेक्षित पाटन और क्षति के संभावना संबंधी विश्लेषण को भी अपनाएंगे।

17. ऊपर बताई गई नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के उपबंध आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे।

ज. सूचना प्रस्तुत करना

18. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देशों की सरकारों, भारत में संबद्ध वस्तु के आयातकों व प्रयोक्ताओं को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना निम्नलिखित को प्रस्तुत करने और प्राधिकारी को अपने विचारों से अवगत कराने का अलग-अलग अनुरोध किया गया है:

निर्दिष्ट प्राधिकारी

व्यापार उपचार महानिदेशालय

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,

5, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

19. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षों को उसे उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश भी प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

झ. समय-सीमा

20. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
21. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जांच की शुरुआत की तारीख से 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपायों को जारी रखने की जरूरत या अन्यथा के संबंध में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

ट. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

22. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और (ख). अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए और साथ ही उनकी साफ्ट प्रतियां भी होनी चाहिए।
23. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां प्रस्तुत करना जरूरी होगा।

24. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए, सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशकरण क्यों संभव नहीं है।
25. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध/रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।
26. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
27. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ठ. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

28. नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

ड. असहयोग

29. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं महानिदेशक

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2019

Case No. SSR 03/2019

Sub: - Initiation of Sunset Review investigation concerning imports of Acetone from Korea RP, Taiwan and Saudi Arabia.

F. No.7/9/2019-DGTR.—1. Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and thereafter (hereinafter referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred as the Rules), the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) recommended imposition of anti-dumping duty on imports of “Acetone” (hereinafter referred as the subject goods), originating in or exported from Korea RP, Taiwan and Saudi Arabia (hereinafter collectively referred to as the subject countries).

2. Whereas, the original investigation concerning imports of the subject goods from the Russia and Korea RP was initiated by the Authority. However, the Authority vide Notification No. 14/13/2006 dated 14th March, 2008 terminated the investigation concerning the subject goods, originating in or exported from Russia. Thereafter,

Final Finding Notification was issued by the Authority vide Notification No. 14/13/2006-DGAD dated 9th May, 2008 recommending imposition of definitive duty against imports from Korea RP. On the basis of recommendations made by the Authority in the final findings, definitive anti-dumping duty was imposed vide Notification No.75/2008-Customs dated 10th June, 2008. A review investigation was carried on thereafter and the Authority recommended continued imposition of duty on imports from Korea RP. The Ministry of Finance extended definitive anti-dumping duty vide Notification No. 05/2015-Customs (ADD) dated 18th February, 2015.

3. Whereas, the original investigation concerning imports of the subject goods from the Taiwan and Saudi Arabia was initiated by the Authority and thereafter, Final Finding Notification was issued by the Authority vide Notification No. 14/16/2012-DGAD dated 22nd January, 2015 recommending imposition of definitive duty. On the basis of recommendations made by the Authority in the final findings, definitive anti-dumping duty was imposed vide Notification No. 13/2015-Customs (ADD) dated 16th April, 2015.
4. Whereas, SI Group India Pvt. Ltd, Hindustan Organic Chemicals Limited and Deepak Phenolics Ltd (hereinafter referred to as 'Petitioners') have filed a combined review petition for continued imposition of Anti-dumping duty on imports of Acetone from Korea RP, Saudi Arabia & Taiwan, in accordance with the Act and Rules.
5. Whereas, based on the facts and data, the Authority is of the opinion that there is a need to review for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the Korea RP, Taiwan and Saudi Arabia.

A. Product under Consideration

6. The product under consideration in the petition is the same as the original investigations, which was defined as follows in the final findings-

"12.The product under consideration (PUC) in the original investigation as well as the present SSR investigation is Acetone. It is a basic organic chemical produced in single grade. It is a colour less liquid with an agreeable ether-like odour. It is used in numerous organic syntheses either as solvent or as an intermediate. It is used in manufacture of bulk pharmaceuticals, agro-chemicals, dyestuffs, certain explosives and downstream chemicals. Acetone is specifically used in manufacture of Isophorone, Diacetone, Alcohol, Methyl Methacrylate and Bisphenol A. Besides this, it is used in manufacture of certain rubber chemicals or Oxy Acetylene Cellulose Acetate."

7. Since the investigation being a sunset review investigation, product under consideration remains the same as defined in the previously conducted investigation. Further, no significant developments have taken place over the period.

B. Like Article

8. Rule 2(d) with regard to like article provides as under: -

"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;

9. Petitioners have claimed that there is no known difference in the subject goods produced by the Indian industry and exported from subject countries. Subject goods produced by the Petitioners and imported from the subject countries are comparable in terms of physical & technical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably.
10. The scope of the product under consideration has been kept the same as was considered by the Designated Authority at the time of previous final findings. Subject goods produced by the petitioner companies are being treated as 'like article' to that being imported from the subject countries for the purpose of the present review investigation.

C. Domestic Industry

11. The petition for initiation of sunset review is being jointly filed by SI Group India Pvt. Ltd., M/s Hindustan Organic Chemicals Limited and Deepak Phenolics Ltd. The production of petitioner companies is 100% of Indian production of the subject goods in the Country, as there are no other producers of the subject goods in India.
12. On the basis of information furnished, the Authority notes that the petitioner companies have made imports of the subject goods from the subject countries during the POI, however, the same are under duty free scheme, as well as for seed marketing purposes and also, are not significant in quantity to affect the domestic market situation. Therefore, the Authority has considered the petitioner companies as Domestic Industry within the

meaning of the Rule 2(b) of the Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 of the Rules supra.

D. Initiation of Sunset Review Investigation

13. Whereas, in view of the duly substantiated application filed and in accordance with Section 9 A (5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority hereby initiates a Sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject countries and to examine whether the expiry of existing duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the Domestic Industry.

E. Subject Countries

14. The duties are in force against Korea RP, Taiwan and Saudi Arabia. In view of the evidence on record with regards to existence of dumping and continuance and likelihood of injury, the scope of the present sunset review investigation will cover Korea RP, Taiwan and Saudi Arabia.

F. Period of investigation

15. The period of investigation (POI) for the present investigation is 1st April 2018 to 31st March 2019 (12 Months) and the injury investigation period is from April 2015 to March 2016, April 2016 to March 2017 and April 2017 to March 2018 and POI. Further, the data beyond POI will also be examined to determine the likelihood of dumping and injury.

G. Procedure

16. The review will cover all aspects of the final findings published vide Notification No. 14/16/2012-DGAD dated 22nd January, 2015 recommending imposition of anti-dumping duty on imports of Acetone from Taiwan and Saudi Arabia and all aspects of the final findings published vide Notification No. No.15/13/2013-DGAD dated 4th December, 2014 recommending imposition of anti-dumping duty on imports of Acetone from Korea RP. The Authority would also undertake likelihood analysis of dumping and Injury as required.
17. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

H. Submission of Information

18. The known exporters in the subject countries, the Government of the subject countries through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Designated Authority
Directorate General of Trade Remedies
Department of Commerce
Ministry of Commerce and Industry
4th Floor, Jeevan Tara Building
5, Parliament Street, New Delhi – 110001

19. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to submit a non-confidential version of the same to be made available to the other parties.

I. Time Limit

20. Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-dumping Rules.
21. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the Domestic Industry's

application regarding the need to continue or otherwise the Anti-dumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

J. Submission of Information on Confidential Basis

22. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire response/ submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non- Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either “confidential” or “non-confidential” at the top of each page and accompanied with soft copies.
23. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and two (02) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.
24. For information claimed as confidential, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.
25. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not 6 susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
26. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
27. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information

K. Inspection of Public File

28. In terms of rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidences submitted by other interested parties.

L. Non-Cooperation

29. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Director General